मेहनतकशों का पैग़ाम | मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

मंदिर की रक्षा पुलिस के जिम्मे	3
गुजरात फाइल्स का खौफ	4
नहीं रुक रही किसानों की आत्महत्या	5
हनुमान बनाम दलित	6
इंस्पेक्टर की शहादत	8

वर्ष 33 | अंक -4 | फ़रीदाबाद | 09-15 दिसम्बर 2018 | फोन : - 9999595632 | ₹2.50

केजरीवाल के स्कूल- नया प्रयोग लेकिन अभी बाकी है पुराना रोग

ग्राउंड जीरो से विवेक की पड़ताल

"हमारी सरकार स्कूल और अस्पताल की सरकार है", ये कहना है तिगाँव फरीदाबाद में जनसभा को संबोधित करने आये दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप पार्टी के सुप्रीमो अरविन्द केजरीवाल का। किसी नेता का ऐसा दावा आज के भारतीय लोकतंत्र में एक सुखद वक्तव्य है। पर ये दावा भी क्या सिर्फ खुद को दिया गया प्रशस्ति पत्र है या जमीनी हकीकत भी यही है, 'मजदूर मोर्चा' टीम ने दिल्ली जाकर ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल की।

प्रथम दृष्टा केजरीवाल की स्कूल रिपोर्ट कार्ड ठीक ठाक प्रदर्शित हो रही है पर क्या जिन पक्षों से मिलकर स्कूल का सम्पूर्ण प्रोफाइल बनता और संचालित होता है, उन सभी को इस सुधार अभियान में शामिल किया गया है? जवाब है नहीं।

दक्षिणी दिल्ली के मांडी और आया नगर स्थित दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंग शानदार लाल टाइल्स से बन गई है। शानदार इसलिए क्योंकि पहले बिल्डिंग के नाम पर टूटती और झड़ती इमारत भर ही थी। केजरीवाल सरकार का दावा है कि अब तक दिल्ली में करीब 8000 नए क्लास रूम स्कूली बच्चों के लिए बनाये जा चुके हैं।

आम आदमी पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रामानंद राय की मानें तो 'आप' एक ऐसी पार्टी है जो नए प्रयोग करने की कुव्वत रखती है और अपने यंग ब्रिगेड के दम पर इन प्रयोगों को सिरे भी चढ़ा रही है। स्कूलों में क्या प्रयोग कर रहे हैं? इसपर रामानंद राय ने बताया कि कई स्कूलों के प्रिंसिपल और अध्यापकों को शिक्षा में अग्रणी माने जाने वाले देश नॉर्वे और फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग में क्या-क्या पक्ष शामिल हैं इसकी पूरी जानकारी रामानंद राय के पास भी उपलब्ध नहीं हो सकी।

राय के अनुसार, जो शिक्षक विदेशों से ट्रेनिंग लेकर वापस आये हैं वे स्कूलों के लिए नए मेंटर तैयार करने में सहायक बनते हैं और इसी प्रकार हर मेंटर को 3-4 स्कूल दिए जाते हैं ताकि ट्रेनिंग का अंश सभी तक पहुँचाया जा सके।

राय ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य की तस्दीक करते हुए कहा कि आप सरकार ने निजी स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी पर जहाँ एक ओर नकेल कसी, वहीं जिन स्कूलों ने बड़ी फीस वापस नहीं ली उन्हें नोटिस दे कर अभिभावकों के पैसे वापस कराये। दिल्ली सरकार के नए एक्सपेरिमेंट में स्कूल का समय समाप्त होने के बाद निजी खेल अकादमी के संचालकों को स्कूल ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाजत बाशर्त दी गयी है। अकादमी, स्कूल ग्राउंड का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब उसमे 50 प्रतिशत बच्चे उसी विद्यालय के हों। विद्यालय के बच्चों से अकादमी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं ले सकती। ऐसा ही प्रयोग संगीत अकादमियों के साथ भी करने की तैयारी है।

एक अन्य आप कार्यकर्ता विपुल ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अध्यापकों और बच्चों पर थोड़ा अनुशासन बनाए रखने के लिए क्लासरूम में कैमरा लगाने का काम जारी है और साथ ही पीटीएम् का प्रावधान भी चल ही रहा है। कुछ अध्यापक इस सख्ती से परेशान हैं क्योंकि ज्यादातर को काम-चोरी की लत जो लगी हुई है। पर फिर भी गेस्ट टीचर को हमारी सरकार 30000 रूपए प्रतिमाह वेतन दे रही है।

आप के इन दोनों कार्यकर्ताओं और स्वयं केजरीवाल के दावों की पुष्टि के लिए हमने दिल्ली सरकार के मुनीरका, मांडी और आया नगर स्थित स्कूलों के स्टाफ, बच्चों और उनके अभिभावकों से आगे बात की।

गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत 28 वर्षीय प्रिया ने बताया कि दिल्ली की वर्तमान सरकार में वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर बात क्लासरूम और आधारभूत संरचना की हो तो अविश्वसनीय कार्य किया गया है। लैब और खेलकूद के ऊपर भी सरकार का विशेष ध्यान रहा है।

45 वर्षीय परमानेंट अध्यापक अशोक कुमार पोपली ने बताया कि अपने अब तक के अध्यापन अनुभव में उन्होंने इतनी गंभीरता पहले की किसी भी सरकार में स्कूल के प्रति नहीं देखी। इस सरकार ने ऑडिटोरियम इत्यादि भी काफी अच्छे बनाये हैं अन्यथा ऑडिटोरियम जैसी व्यवस्था तो सिर्फ बड़े निजी विद्यालयों का पेटेंट था। सरकार से पैसा बहुत आ रहा है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए ये प्रिंसिपल पर निर्भर करता है।

अभिभावक रामबीर सिंह चंचल ने भी इसी स्वर में कहा, भाई ऐसा है हमे तो के मतबल सकूल तै, हां बालकां धोरे कदी-कदी पता चले है कि के हो रा है। बिल्डिंग तो घनी बढिया बना दी, होर भी ना जाने के-के करन लाग रे हैं। पर भई म्हारी घरवाली पहले तो बोला करे कि बाल्कन ने पब्लिक सकूल में डाल दऊं पर इब तै ना बोला करे। फेर मतलब जो ही है कि बढ़िया है घर के पास का स्कूल ही।

शेष पेज दो पर

केजरीवाल की कांवर-तीरथ सरकार

हरियाणा में 'गीता भक्त' मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले 'शिव भक्त' अरविन्द केजरीवाल का राजनीतिक पदार्पण हो चुका है। यह दीगर बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव में खट्टर की घोर नाकारा सिद्ध हुयी भाजपा सरकार का जाना तय है और राज्य में आप पार्टी की बागडोर 'पंडित' नवीन जयहिंद के हाथ में रहते शायद ही केजरी का खाता भी खुले।

जयहिंद ने अपनी राजनीतिक मार्केटिंग कांवर के मौसम में स्वयं को कांवर ढोते हुए जगह-जगह फोटो खिंचवा कर शुरू की। जब उस दौरान केजरीवाल रोहतक पहुंचे तो उन्हें भी शिव मंदिर में जल चढाते हुए को मीडिया इवेंट बनाया गया। यानी केजरी और जयहिंद ने हरियाणा में भाजपा के 'हिन्दू कार्ड' के जवाब में अपना 'हिन्दू कार्ड' आगे करने का पैंतरा आजमाया है।

इस बीच केजरीवाल ने दिल्ली में भी, जहाँ वे सरकारी पैसे से अपनी छवि निर्माण के लिए बदनाम रहे हैं, स्वयं को 'धर्मावतार' सिद्ध करने की ठान ली है। उनकी दिल्ली सरकार वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने जा रही है। धर्म की आड़ में ऐसे साम्प्रदायिक पाखंड बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार कर चुकी है और इसके बावजूद वह चुनाव हारने के करीब है। लिहाजा इस कदम को केजरी की हताशा ही माना जाएगा न कि मास्टर स्ट्रोक। राहुल गांधी की तर्ज पर केजरीवाल भी 'हिन्दू' नेता की छवि में उतरेंगे तो देर-सबेर भाजपा उन्हें हजम कर जायेगी। राहुल गांधी की कांग्रेस का एक मजबूत सेक्युलर आधार है जो केजरी को अभी बनाना है। सबसे बड़ा सवाल तो केजरीवाल से यह है कि क्या अब वे 'स्कूल-अस्पताल सरकार' नहीं 'कांवर-तीरथ' सरकार के नाम पर वोट माँगने निकलेंगे?

केजरीवाल के एजेंडे से भी नदारद है ईएसआई कवर्ड मज़दूर

दिल्ली में चिकित्सा सेवाओं को बेहतर करने का दावा करने वाले वहां के मुख्यमंत्री केजरीवाल, हरियाणा में सत्तारूढ होने पर यहां भी चिकित्सा सेवा को बेहतरीन करने के जो तर्क दे रहे हैं उनमें ईएसआई कवर्ड मजदूरों का कोई जिक्र नहीं है। उन्हें शायद इस बात का कोई ज्ञान नहीं है कि हरियाणा में करीब 30 लाख मज़दूर ऐसे हैं जो ईएसआई के दायरे में आते हैं। कानूनन जो श्रमिक 21000 रुपये तक मासिक वेतन पाते हैं, उनके वेतन का साढे छ:प्रतिशत हर माह ईएसआई कार्पोरेशन झटक लेती है। इस हिसाब से राज्य के मज़दूरों का करीब 400 करोड़ रुपया सालाना ईएसआई कार्पोरेशन झटक लेती है।

इसके बदले ईएसआई मज़दूरों को मुफ़्त चिकित्सा सेवा तथा कुछ मामलों में पेशन आदि की सुविधा प्रदान करती है। लेकिन चिकित्सा राज्य का विषय होने के चलते ईएसआई ने यह काम राज्य सरकार के हवाले कर रखा है। यानी कि हरियाणा में रहने वाले तमाम श्रमिकों को चिकित्सा सेवा राज्य सरकार उपलब्ध करायेगी लेकिन इस पर होने वाले कुल खर्च का केवल आठवां भाग ही राज्य सरकार और शेष ईएसआई कार्पोरेशन खर्च करेगी। यानी राज्य सरकार 800 करोड़ का बजट बनाये तो उसे केवल 100 करोड़ तथा शेष 700 करोड़ ईएसआईसी को खर्च करना होगा। इस के लिये राज्य सरकार ने बाकायदा ईएसआई हैल्थ केयर निदेशालय खड़ा करके उसमें करीब 100 लोग़ों का स्टाफ़ बैठा रखा है। इस निदेशालय का दायित्व है कि वह राज्य भर में ईएसआई कवर्ड श्रमिकों के लिये पर्याप्त मात्रा में डिस्पेंसरियां व अस्पताल आदि खोले। इस काम के लिये उसे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर व अन्य स्टाफ़ भर्ती करने, तमाम तरह के आवश्यक उपकरण व साजो-सामान तथा दवायें आदि खरीदने का अधिकार है।

अपने इस दायित्व को सही ढंग से निभाने के लिये राज्य सरकार के इस निदेशालय को कम से कम 1200 करोड़ का बजट बना कर 150 करोड़ खुद तथा शेष 1050 करोड़ ईएसआईसी से लेने चाहिये। परन्तु राज्य सरकार की अनदेखी, मूर्खता या जनविरोधी नीति के चलते उक्त निदेशालय अपना बजट 125-150 करोड़ से अधिक कभी नहीं बनाता, बल्कि वर्ष के अन्त में इस बजट में से भी 5-10 करोड़ रुपया लैप्स हो जाता है। जाहिर है सरकार की इस कुनीति के चलते राज्य भर में न तो पर्याप्त डिस्पेंसरियां है और न ही अस्पताल, जो हैं भी वे किसी काम के नहीं क्योंकि वहां न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं न कोई उपकरण आदि। इसका ज्वलंत उदाहरण सेक्टर 8 (फ़रीदाबाद) का ईएसआईसी अस्पताल है।

30 लाख ईएसआई कवर्ड का अर्थ होता है 30 लाख परिवार राज्य भर में कुल 46-47 लाख परिवार हैं। यदि सरकार की अक्ल से दुश्मनी न हो तो वह ईएसआईसी के खर्चे पर अपनी आधी से ज्यादा आबादी को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा प्रदान कर सकती है। परन्तु सरकार का लक्ष्य चिकित्सा सुविधा देने की अपेक्षा 'आयुष्मान भारत' जैसी जुमलेबाज़ी करने का रहा है। लेकिन केजरीवाल द्वारा भी इस विषय पर खामोश रहना एवं अनदेखी करने से लगता है कि श्रमिक वर्ग उनकी प्रथमिकता में कहीं नहीं आता।

बीके में कैदी को जेल से अस्पताल में भर्ती कराने का सौदा

फ़रीदाबाद (म.मो.) ज़िले के सबसे बड़े सरकारी बादशाहखान अस्पताल में आने वाले मरीज़ों की जो ऐसी-तैसी रोज़ाना होती है उसकी रिपोर्टें तो पाठक पढते ही रहते हैं। अभी प्राप्त विश्वस्त जानकारी के अनुसार बीते 25 दिन से नीमका जेल में पड़े एक बंदी ने जेल की बजाय बीके अस्पताल के बेड पर रहने का जुगाड़ बनाया है।

संजीव ढींगड़ा नामक बिल्डर ने नहर पार के सेक्टर 80 में ढींगड़ा एंड जार्डन नामक एक हाउसिंग सोसायटी बना कर 490 लोग़ों को फ़्लैट बना कर देने के सपने बेचे थे। लोग़ों से करोड़ों रुपये हड़पने के बावजूद जब बरसों तक ढींगड़ा ने उन्हें कुछ नहीं दिया तो ठगी के शिकार लोग़ों ने उसके विरुद्ध धोखा-धड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने उसे 12 नवम्बर को गिरफ़्तार कर नीमका जेल भिजवा दिया। अदालत में जमानत न हो पाने और जेल की जिंदगी से परेशान ढींगड़ा ने बीके अस्पताल के एक फ़ार्मासिस्ट से मिल कर अस्पताल में भर्ती होने का जुगाड़ बनाया है।

जाहिर है ऐसे काम कोई मुफ़्त में तो होते नहीं तथा लेन-देन की कोई रसीद या गवाही भी नहीं होती। लेकिन भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार यह सौदा 5 लाख में तय हुआ है। यह जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है कि इस रकम में किसका कितना हिस्सा है। सीएमओ डॉक्टर सहरावत का भी इसमें कोई हिस्सा है या नहीं लेकिन उन्होंने हड्डियों के डॉक्टर गौड़ व एक-दो अन्य डॉक्टरों पर

सीएमओ वीर सिंह

ढींगड़ा को दाखिल करने का दबाव बना रखा है। लेकिन इस दबाव के बावजूद कोई डॉक्टर यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं। तयशुदा रणनीति के अनुसार ढींगड़ा किसी बीमारी का बहाना बना कर तभी जेल से बीके अस्पताल आने वाला है जब कोई डॉक्टर उसे दाखिल करने को तैयार हो जायेगा।

बीके अस्पताल की भीतरी जानकारी रखने वाले जानकार बताते है कि उक्त फ़ार्मिसिस्ट बीते कई माह से किसी मलाईदार सीट पर बैठने की जीतोड़ कोशिश में है। पूर्व सीएमओ गुलशन अरोड़ा को तो उसने एक डीसीपी से भी फ़ोन करवाया था लेकिन बात नहीं बनी। उनके बाद आये दोनों सीएमओ ने भी उसे घास नहीं डाली। अब कहीं जाकर मौजूदा सीएमओ ने उसे मुंह लगाया है। इसके चलते उसने एमआरआई व सीटी स्कैन वाली कम्पनी तथा कैथ लैब वाली कम्पनी से 10 प्रतिशत की वसूली करके उनके 50-60 लाख रुपये के सरकारी बिल निकलवा दिये। लेकिन डायलेसिस वाली कम्पनी ने यह 10 प्रतिशत नहीं दिया तो उसके बिल सीएमओ साहब रोके बैठे हैं।

इसी तर्ज पर, उसी सुषमा नामक नर्सिंग सिस्टर को फ़िर से जच्चा-बच्चा वार्ड में तैनात करा दिया गया जिसको मोटी लूट-मार के चलते वहां से हटाया गया था। सुषमा अपनी लूट-मार का धंधा निर्बाध रूप से चलाती रह सके, इसके लिये, उसके रास्ते की बाधा रिम्पी नामक स्टाफ़ नर्स को भी वहां से हटा दिया गया। अब कोई कैसे विश्वास करे कि सीएमओ साहब, जो इसी माह रिटायर होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये सब उल्टे-पुल्टे काम मुफ़्त में ही कर रहे हैं?

समाचार लिखते-लिखते पता चला है कि ढींगड़ा जेल से आकर सात तारीख को अस्पताल में भर्ती हो चुका है। यद्यपि डा. गौड़ तो सीएमओ के दबाव में नहीं आये लेकिन यहां पर नये-नये आये डा. बैनीवाल जोकि सर्जन है, सीएमओ के दबाव में आ गये और ढींगड़ा को भर्ती कर लिया। डा. बैनीवाल ने यह गलत काम केवल सीएमओ के दाबव में ही किया है या उक्त रकम में से अपना हिस्सा लेकर किया है। इसका पता अभी नहीं चल पाया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जब डाक्टर बैनीवाल को अपनी गलती का अहसास हुआ तो उन्होंने आठ दिसम्बर को ढींगड़ा को डिस्चार्ज भी कर दिया था लेकिन सीएमओ के अत्यधिक दबाव के चलते दोबारा भर्ती करना पड़ा।